साप्ताहिक

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

RNI-MPHIN/2015/72544

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार 04-11 अप्रैल 2022, वर्ष-8, अंक-1

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठ :-8, मूल्य :- 2 रुपए

सहकारी बैंकों का 60 करोड़ ब्याज भरेगी सरकार, मध्यप्रदेश में 96 सौ करोड़ की ऋण वापसी नहीं हुई

डिफाल्टर होने से बच गए प्रदेश के दस लाख किसान

भोपाल। प्रशासनिक संवाददाता

प्रदेश में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से दिए जाने वाले खरीफ फसलों के ऋण की अदायगी किसान अब 15 अप्रैल तक कर सकेंगे। सरकार ने दस लाख किसानों को डिफाल्टर होने से बचाने के लिए यह अवधि 28 मार्च से बढ़ा दी है। यह निर्णय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। इससे सरकार के ऊपर लगभग 60 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। सरकार के प्रवक्ता गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि किसान खरीफ सीजन के लिए शून्य प्रतिशत पर लिया गया ऋण समय पर नहीं चुकाते हैं तो वे डिफाल्टर हो जाते हैं। इस स्थिति को देखते हुए ऋ ण अदायगी की अंतिम तारीख 28 मार्च को बढ़ाकर 15 अप्रैल करने का निर्णय लिया गया है। इस अवधि के ब्याज का भुगतान सरकार करेगी। सहकारिता विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 11 हजार करोड़ रुपए से अधिक का अल्पावधि ऋण किसानों को दिया गया है। अभी तक 22 प्रतिशत वसूली हुई यानी 96 सौ करोड़ की ऋण वापसी नहीं हुई है।

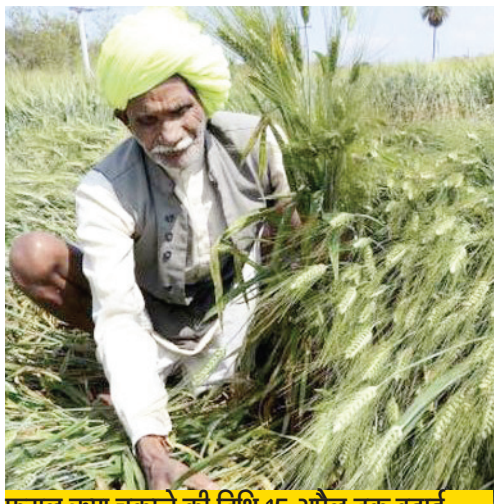

फसल ऋण चुकाने की तिथि 15 अप्रैल तक बढ़ाई

28 मार्च को खरीफ का ऋण चुकाने का समय समाप्त

दस रुपए में नक्शा-खसरा

यह भी तय किया गया अब मध्य प्रदेश में दस रुपए में नक्शे, खसरे जैसे दस्तावेज मोबाइल पर उपलब्ध होंगे। इसके साथ ही 181 के माध्यम से लोक सेवा गारंटी की सुविधा मोबाइल पर प्रदान की जाएगी। अब वाट्सएप पर खसरे, नक्शे, ऋण पुस्तिका जैसे दस्तावेज की कॉपी मिल सकेगी।

खरीफ की फसल के लिए लिए गए ऋण को कई किसान चुका नहीं पाए हैं। अवधि समाप्त होने के बाद वे डिफाल्टर हो जाएंगे। इसलिए हमने तिथि को 15 अप्रैल बढ़ा दी है। ब्याज का 60 करोड़ भी राज्य सरकार भरेगी। यही नहीं, अब 10 रुपए में नक्शे, खसरे जैसे दस्तावेज मोबाइल पर मिलेंगे।

शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में किसान भाइयों के हित में फसल ऋण (खरीफ) चुकाने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 15 अप्रैल कर दिया गया है। अवधि बढ़ाने से लगने वाले ब्याज की राशि लगभग 60 करोड़ रुपए होगी, जिसे राज्य सरकार भरेगी।

कमल पटेल, कृषि मंत्री

किसानों को ज्यादा से ज्यादा आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध होंगे

मध्य प्रदेश में खोले जाएंगे तीन हजार नए कस्टम हायरिंग सेंटर

भोपाल। संवाददाता

कृषि के क्षेत्र में मशीनों का उपयोग बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना कर रही है। जिसके लिए किसानों, उद्यमियों, सहकारी समितियों एवं ग्राम पंचायतों को कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना के लिए अनुदान दिया जाता है। इन केंद्रों से किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार किराए से कृषि यंत्र ले सकते हैं। इससे जहां किसानों को कम दरों पर कृषि यंत्र मिल जाते हैं वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार भी उपलब्ध होता है। लोकसभा में सांसद उदय प्रताप सिंह ने मध्य प्रदेश में नए कस्टम हायरिंग सेंटर, कौशल विकास केंद्र एवं यंत्र दूत की स्थापना को लेकर सवाल किए थे। जिसके जवाब में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बताया कि मध्य प्रदेश में 3,000 नए कस्टम हायरिंग खोलने जा रही है। जिससे किसानों को ज्यादा से ज्यादा आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध हो सकेंगे। साथ ही राज्य में कौशल विकास केंद्रों की स्थापना भी की जाएगी।

600 नए कृषि यंत्र प्रणाली स्थापित करेंगे

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन की यंत्रदूत ग्राम योजना के तहत 600 ग्रामों में यंत्रीकृत कृषि प्रणाली स्थापित करने का भी लक्ष्य रखा गया है। जिसके अंतर्गत नियोजित तरीके से प्रशिक्षण एवं भ्रमण कार्यक्रमों के साथ -साथ बड़े स्तर पर क्लस्टर प्रदर्शनों का आयोजन किया जाता है।

10 लाख तक का अनुदान

मध्यप्रदेश में किसानों को 25 लाख तक के कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना पर सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है। योजना के तहत कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने के लिए किसानों को 40 प्रतिशत अधिकतम 10 लाख तक का क्रेडिट लिंक्ड बेक एंडेड अनुदान दिया जाता है। अनुदान की गणना सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन योजना में प्रत्येक यंत्र के लिए दिए गए प्रावधान के अनुसार दिया जाता है।

खुलेंगे कौशल विकास केंद्र

कृषि मंत्री ने बताया कि नए वित्त वर्ष में मध्य प्रदेश में 3,000 नए कस्टम हायरिंग सेंटर खोले जाएंगे। इसके अलावा राज्य में कौशल विकास केंद्र की स्थापना भी किया जाएगा। मौजूदा समय में राज्य में भोपाल, जबलपुर, सतना, सागर और ग्वालियर संभागों में कौशल विकास केंद्र संचालित किए जा रहे है। आगे वित्त वर्ष में उज्जैन, नर्मदापुरम, चंबल और शहडोल संभागों में 4 नए कौशल विकास केंद्र शुरू करने का लक्ष्य है।

कृषि विभाग से सहायता नहीं मिलने के कारण किसानों का मोहभंग

ब्रांडिंग के बाद भी घट गया कोदो-कुटकी का उत्पादन

भोपाल। संवाददाता

पौष्टिकता से भरपूर कोदो-कुटकी की खेती के लिए प्रदेश सरकार किसानों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है। लेकिन किसानों को इसके लिए कोई सरकारी सहायता नहीं मिल रही है। इस कारण किसानों का कोदो-कुटकी की खेती से मोहभंग हो रहा है। जिसका परिणाम है कि पिछले तीन साल में कोदो-कुटकी का उत्पादन 11 हजार मीट्रिक टन घट गया है। गौरतलब है कि कोदो-कुटकी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए 2019 में विश्व व्यापार मेले में मृगनयनी एम्बोलिका द्वारा एक स्टॉल भी लगाई गई। अनूपपुर में एक दुकान भी खोली गई थी। साथ ही सरकार हमेशा कोदो-कुटकी की ब्रांडिंग की बात करती है, लेकिन इसमें दिखावा ही किया जा रहा है, क्योंकि किसानों को इसके लिए सरकारी मदद नहीं मिलती। इस कारण किसान कोदो-कुटकी की खेती से परहेज करने लगे हैं।

साल दर साल कम हो रहा उत्पादन | प्रदेश में सरकार की कोशिशों के बावजुद कोदो-कुटकी का उत्पाद साल दर साल कम हो रहा है। तीन साल में उत्पादन 73 हजार से घटकर 62 हजार मीट्रिक टन रह गया है। वर्ष 2019-20 में जहां 73 हजार मीट्रिक टन उत्पादन हुआ था। वहीं 2020-21 में 69 हजार मीट्रिक टन और 2021-22 में 62 हजार मीट्रिक टन कोदो-कुटकी का उत्पादन हुआ है। कृषि विभाग इसकी ब्रॉडिंग तो बहुत करता है, लेकिन आदिवासी किसानों को इसके लिए कोई मदद नहीं दी जाती, जबकि पर्यटन निगम नेशनल पार्कों के आसपास स्वसहायता समूहों के माध्यम से ब्रॉडिंग का काम कर रहा है, जिससे विदेशी पर्यटकों को लुभाया जा सके।

लघु वनोपज संघ कोदो- कुटकी को बाजार उपलब्ध कराने का काम करता है, लेकिन इसका उत्पादन आदिवासी ही करते हैं और ब्रॉडिंग का काम कृषि विभाग द्वारा किया जाता है।

पुष्कर सिंह, पीसीसीएफ,लघु वनोपज संघ

कोदो-कुटकी के लिए स्थानीय स्तर पर प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने के साथ ही आउटलेट की दुकान खोली गई है। अब तक समर्थन और बेहतर बाजार का अभाव होने के कारण किसान ज्यादा रुचि नहीं दिखा रहे।

एनडी गुप्ता, उपसंचालक कृषि

सुपर ऐप करेगा किसानों की हर समस्या का समाधान

भोपाल/नई दिल्ली। किसानों के विकास और उनकी सहूलियत के लिए सरकार किसानों के लिए एक सुपर ऐप लॉन्च करने की योजना बना रही है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अधिकारी का कहना है कि इस ऐप में कई डिजिटल संस्थाएं और मौजूदा मोबाइल ऐप्स को भी शामिल किया जाएगा। इस तरह से यह ऐप एक तरह का प्लेटफार्म होगा, जहां एक ही छत के नीचे सभी तरह की समस्याओं के समाधान मिल सकेगा। यानी नए शोध से लेकर विकास, मौसम, बाजार, अपडेट उपलब्ध सेवाएं, सरकारी योजनाएं और जलवायु के क्षेत्र से जुड़ी हर जानकारी किसानों को एक ही ऐप के माध्यम से मिल सकेगी।

सेवाएं चुनने में मदद होगी | कृषि मंत्रालय किसान सुविधा, पूसा कृषि, एमकिसान, फार्म ओ पीडिया, क्रॉप इंश्योरेंस एंड्राइड एप एग्रीमार्केटए इफ्को किसान और आईसीएआर कृषि ज्ञान जैसे तमाम ऐप्स को एक साथ जोड़ने के बारे में विचार कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि सुपर ऐप के तहत सारी ऐप्स के आ जाने से किसानों को सेवाएं चुनने में मदद होगी। इस ऐप को लाने का मकसद ही यही है कि किसानों को संबंधित ऐप को खोजने में आसानी रहे।

साल भर की खेती: गेंदे का फूल 10 से लेकर 60 रुपए प्रति किलो की दर से मिलता है भाव, रोग भी बेअसर

-तीखी मिर्च भी घोल सकती है मिठास, लागत की तुलना में ढाई से तीन गुना किसान कर सकते हैं कमाई

गेंदा और मिर्च की खेती से किसान होंगे आत्मनिर्भर

जबलपुर। संवाददाता

किसान परंपरागत खेती के साथ फूलों की खेती कर अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। गेंदे के फूल की खेती साल भर किसान कर सकते हैं। बस सिंचाई का साधन होना चाहिए। पूरे साल फूलों की डिमांड बनी रहती है। त्यौहार और शादी-विवाह के मौसम में इसकी मांग और बढ़ जाती है। किसानों को 10 से 60 रुपए प्रति किलो का भाव मिल सकता है। वहीं हरी मिर्च का उपयोग दुनियाभर में होता है। बाजार में इसकी मांग सालभर रहती है। मिर्च का जायका तीखा होता है, लेकिन ये किसान की जिंदगी में मिठास घोलने वाली फसल है। साल में तीन बार इसके पौधे रोप सकते हैं। इसके बाद साल भर कमाई होती है। इसका उपयोग अचार, मसाले, सब्जी, औषधीय और सॉस बनाने में होता है। मिर्च 40 रुपए से लेकर 100 रुपए से ऊपर की कीमत पर बिक जाती है। ये ऐसी फसल है कि किसान की जेब में रोज आमदनी होती है। गेंदे के फूलों और मिर्च की खेती किसान कैसे करें। '**जागत गांव हमार**' के इस अंक में जवाहर लाल नेहरू कृषि विवि जबलपुर के रिटायर कृषि वैज्ञानिक डॉ. एके नायडू ने अपने अनुभव साझा किए हैं।

नायडू के अनुसार, प्रगतिशील किसान अपनी खेती के एक हिस्से में फूलों की खेती कर अच्छी कमाई कर सकते हैं। फूलों की खेती कई तरह से कर सकते हैं। पानी की सुविधा तो तो खेती के कुछ हिस्से में फूल लगाकर रेगुलर कमाई कर सकते हैं। बाजार में पूजा, त्यौहार और शादी-विवाह के सीजन में इसकी मांग अधिक बढ़ जाती है। उसी अनुसार कीमत भी मिलता है।

मिट्टी के अनुसार गेंदे की किस्म चुने

गेंदे की कई किस्में आती हैं। किसान क्षेत्र के अनुसार आरेंज व यलो कलर वाले गेंदे का चुनाव कर सकते हैं। किस्म ऐसा चुने, जो कम बीमारी वाले हो और वहां की मिट्टी को सूट करता हो। सिंचाई के लिए टपक पद्धति का उपयोग करना चाहिए। इससे पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रहता है। पानी व खाद का प्रयोग एक तय मानक के अनुसार कर आप उत्पादन बढ़ा सकते हैं।

मल्च लगाकर करें पौधे की रोपाई

जब पौधा 10-15 सेमी और 3-4 पत्तियों का हो जाए तब इसकी रोपाई करें। सामान्यत: 25-30 दिन में पौधा रोपाई के लायक हो जाता है। रोपाई के बाद हल्की सिंचाई करें। गेंदे के पौधे को 45 सेमी की दूरी पर रोपे। एक हेक्टेयर में रोपाई करने के लिए 50 से 60 हजार पौधे की जरूरत पड़ेगी। गेंदे के फूल की खेती मल्च लगाकर करें। इसका दोहरा फायदा है। पहला कि इससे कचरा नहीं होता। दूसरा रिवर्स हीट से कीड़े नहीं लगते हैं।

मिर्च में लागत और कमाई का फंडा

हरी मिर्च की खेती नगदी फसल है। मिर्च की उन्नत किस्मों को उगाने के साथ ही फसल की सुरक्षा के उचित उपाय करें, तो लागत की तुलना में दोगुनी कमाई कर सकते हैं। हरी मिर्च की एक एकड़ खेती की लागत औसतन 35-40 हजार रुपए आती है। वहीं, एक एकड़ में औसतन उपज 60 क्विंटल तक हो जाती है। बाजार में यह 20 से 100 रुपए के बीच में बिकता है। ऐसे में किसान को डेढ़ से दो लाख की कमाई हो सकती है।

अगस्त में लगाया, सितंबर में फल

नायडू ने बताया कि मैंने अपने खेत में 15 अगस्त को मिर्ची लगाई थी। सितंबर से फलन शुरू हो गया। आठ से नौ महीने तक उत्पादन मिलता है। शुरुआती में थ्रिप्स का रोग लगता है। ये मिर्च का प्रमुख रोग है। इसे झुलसा रोग भी बोलते हैं। इससे फसल को बचा लें तो फिर रोज कमाई का जरिया बन जाता है। शुरुआत में 20 रुपए किलो पर बिकने वाला मिर्च गर्मियों में 80 से 100 रुपए पर बिकता है। ऐसे में किसानों को औसतन 40 रुपए के लगभग भाव पड़ता है।

ग्रामीणों को मिला रोजगार

मिर्च देखना अच्छा लगता है, पर तुड़ाई थोड़ी मुश्किल होती है। दरअसल, तीखापन के चलते परेशानी होती है। इस कारण मिर्च की तुड़ाई का ठेका होता है। तीन से चार रुपए प्रति किलो की दर से तुड़ाई का ठेका देते हैं। एक आदमी 35 से 40 किलो एक दिन में तोड़ देता है। फिर इसे लोड कर पास के मंडी में पहुंचा देते हैं।

सेहत के लिए फायदेमंद

मिर्च में तीखापन कैप्साइसिन नामक तत्व के कारण होता है। हरी मिर्च की खेती से किसान कम लागत में अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। मिर्च का उपयोग कई प्रकार की दवाइयों बनाने में किया जाता है। कैप्साइसिन में कई दवाइयां बनाने वाले तत्व मिलते हैं। खासतौर पर कैंसर रोधी और दर्द दूर करने वाले तत्व इसमें मिलते हैं। मिर्च में विटामिन ए, सी, फॉस्फोरस और कैल्शियम भी पाया जाता है।

15 मई से साल भर खेती| गेंदे की फसल 15 मई से लेकर साल भर कभी भी कर सकते हैं। गेंदे में 35 से 40 दिन में फूल आने लगते हैं। डॉक्टर नायडू ने खुद अपने आधा एकड़ खेत में गेंदे का फूल लगाया है। अभी तक एक तुड़ाई हुई है। दो क्विंटल फूल निकला है। 6 हजार रुपए की कमाई हुई है। एक पौधे से 25 से 30 बार फूलों की तुड़ाई होती है। मेडिसनल प्लांट होने के चलते इसमें कीड़े भी कम लगते हैं। दूसरी स्वाइल बांड डिजिज भी इससे चेक होती है। इसे फसल के बीच में भी लगा सकते हैं।

हरी मिर्च की खेती का सही समय

हरी मिर्च की खेती को साल में 3 बार उगाया जा सकता है। हरी मिर्च की खेती के लिए जून-जुलाई, सितंबर-अक्टूबर और फरवरी-मार्च का समय उपयुक्त होता है। एक बार पौधे की रोपाई के बाद नौ महीने तक पैदावार मिलता है। मिर्च की रोपाई से पहले खेत की तैयारी करनी चाहिए। जुताई के समय 300-400 क्विंटल गोबर की खाद प्रति एकड़ मिला दें। इसके बाद चार फीट की दूरी पर क्यारी बना लें। मेड़नुमा वेड बना कर उसे मल्चिंग और सिंचाई के लिए टपक विधि की पाइप बिछा दें।

फूल की खेती से पहले करें तैयारी| गेंदे के फूल की खेती से पहले खेत की गहरी जुताई करनी चाहिए। इसके बाद प्रति हेक्टेयर 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद का प्रयोग करें। फिर 50 किलो नाइट्रोजन, 200 किलो फॉस्फोरस, 200 किलो पोटाश को मिट्टी में मिला सकते हैं। रोपाई के बाद टपक विधि से पानी के साथ खाद दे सकते हैं। गेंदा हर मौसम में उगाया जा सकता है। इस कारण सर्दी में 8 से 10 दिन और गर्मी में पांच से 7 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। फूल आने पर सिंचाई करते रहें। पानी की कमी से फूल का उत्पादन प्रभावित होगा।

दमोह के एक प्रगतिशील किसान ने शुरू की खेती

बड़े शहरों के बाजार में दिनों-दिन बढ़ रही मांग, कृषि विवि 7 दिन में कर देती है किसान को दक्ष

मोती की खेती से चमकेगी किसानों की किस्मत

इधर, किसान मोती की खेती कर अच्छी कमाई कर सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू कृषि विवि के छिंदवाड़ा सेंटर में मोती की खेती की ट्रेनिंग दी जाती है। कृषि विज्ञान केंद्र चंदनगांव छिंदवाड़ा में कोई भी व्यक्ति 5 से 7 दिन की ट्रेनिंग लेकर मोती की खेती का गुर सीख सकता है। यहां एक साल पहले मोती की खेती की गई है, जो जुलाई में तैयार होगी। बाजार में एक मोती 200 से 1000 रुपए के बीच क्वालिटी के मुताबिक बिकता है। मोती की खेती किसान कैसे करें। इसकी पूरी विधि बता रही हैं कार्यक्रम सहायक, जेएनकेवीवी (कृषि विज्ञान केंद्र चंदनगांव छिंदवाड़ा की विशेषज्ञ डॉ. चंचल भार्गव। उन्होंने बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (नई दिल्ली) से प्राप्त आदिवासी उपयोजना के तहत मोती की खेती शुरू की गई। राजस्थान से 8 हजार सीपों को मंगाकर एक छोटी सी सर्जरी कर मार्च 2021 में बीजों को डाला गया। इस साल जुलाई या अगस्त में मोती तैयार हो जाएंगे। इस सेंटर में अभी तक मप्र के सभी जिलों के अलावा पंजाब, हरियाणा, यूपी, भुवनेश्वर के किसानों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। प्रदेश में दमोह के एक प्रगतिशील किसान ने इसकी खेती शुरू भी कर दी है।

इस तरह करें मोती की खेती

किसान खेत में 5000 वर्गफीट का तालाब 12 फीट गहराई में खुदवा लें। बारिश से पहले खुदवाना ठीक रहता है। इसमें 10 हजार सीपों को डाला जा सकता है। एक सीप की कीमत 10 रुपए पड़ती है। इससे ये बारिश में नेचुरल हो जाएगा। बारिश के बाद सीपों को डालना चाहिए। पहले सीप को लाकर 25 दिन से एक महीने तक तालाब में डाल दें, जिससे वे यहां के मौसम के अनुकूल हो सकें। सीप डालने से पहले तालाब को कल्चर करना पड़ता है। इसके लिए इसमें गोबर का घोल और सीप के भोजन के लिए समुद्री शैवाल का चूरा डालना चाहिए।

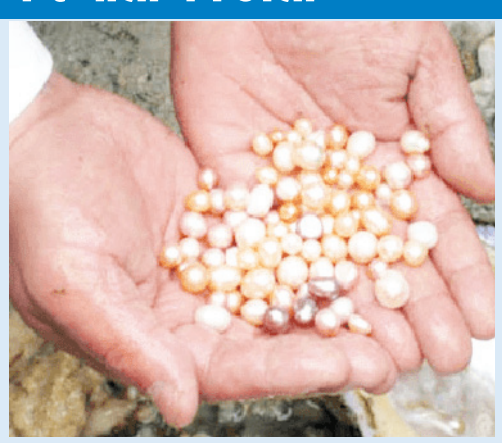

2700 रुपए का पांच किलो समुद्री शैवाल

बाजार में समुद्री शैवाल का 5 किलो का डिब्बा 2700 रुपए में आता है। ये डेढ़ महीने की खुराक है। ये शैवाल ही सीप का भोजन है। एक महीने के बाद सीप में सर्जरी कर पर्ल न्यूक्लियस को डालते हैं। पर्ल न्यूक्लियस सीप को पीस कर उसके चूरे में केमिकल मिलाकर तैयार किया जाता है। इसे सांचें में डालकर गोल या डिजाइनदार गणेश, बुद्ध, पुष्प की आकृति दे सकते हैं।

तालाब का पानी हरा रहना चाहिए

मोती की खेती में सबसे सावधानी पानी के मानक को बनाए रखना है। तालाब में शैवाल बने। पानी का पीएच स्तर 7-8 के बीच रखें। यदि अमोनिया शून्य नहीं है, तो 50 प्रतिशत पानी बदलें या स्तरों को बढ़ाने के लिए चूना मिलाएं। पानी का ऑक्सीजन लेवल बनाए रखना होगा। इससे सीप अच्छे से सरवाइव कर जाते हैं। 80 फीसदी सीप बचेंगे।

मोती की खेती से कमाई का फंडा

मोती का बाजार जयपुर और हैदराबाद है। कृषि विज्ञान केंद्र चंदनगांव छिंदवाड़ा ने पहले ही एक एजेंसी से 100 रुपए प्रति मोती बेचने का अनुबंध कर लिया है। 5000 वर्गफीट वाले तालाब में 10 हजार सीप से यदि मोती की खेती किसान करते हैं तो सर्जरी के बाद लगभग 8000 सीप बचेंगे। प्रति सीप औसतन दो मोती जोड़े तो 18 महीने बाद 16 हजार मोती मिलेंगे। 100 रुपए की दर से इसकी कीमत होती है 16 लाख रुपए, जबकि तालाब से लेकर सारा खर्च 6 से 7 लाख का होता है। तालाब का खर्च पहले साल ही आएगा। इसके बाद किसान अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।

मोती निकालने के बाद सीप का भी उपयोग

मोती निकालने के बाद मृत सीप के खोल का भी उपयोग होता है। इससे बटन बनाने से लेकर चूरा बनाकर मुर्गियों या मछलियों के लिए आहार के रूप में उपयोग हो सकता है। पूरा खोल ही कैल्शियम का होता है। इसी को पीस कर केमिकल मिलाकर पर्ल न्यूक्लियस भी तैयार किया जाता है। पर्ल न्यूक्लियस भी बनाकर बेच सकते हैं।

नरवाई और बायलरों में जला दिया पशुओं का भोजन

हरे चारे की कमी, पशु गेहूं व चने के भूसे पर निर्भर

मध्यप्रदेश में घट गया 15-20 फीसदी दूध

इंदौर। संवाददाता

हमने लालच में पशुओं के भोजन को ईंधन बना डाला तो पशुओं ने भी इसका प्रतिफल दे दिया। प्रदेश के किसानों और उद्यमियों के लालच में पशुओं का अधिकांश चारा नरवाई में जला दिया गया या कारखानों के बायलरों में ईंधन के रूप में फूंका गया। परिणाम सामने है, इस समय मध्यप्रदेश का दूध उत्पादन लगभग 15-20 प्रतिशत घट गया है। जनवरी-फरवरी तक सब ठीक-ठाक था, लेकिन मार्च अंत से ही दूध की यह गिरावट साफ दिखने लगी है। मप्र में हरे चारे की कमी है। ऐसे में अधिकांश दूध उत्पादक दुधारू पशुओं के लिए गेहूं और चने के भूसे पर ही निर्भर हैं। पर कई किसानों ने हार्वेस्टर से गेहूं कटवाने के बाद या तो भूसे को खेत में ही जला दिया या भूसे के कई बड़े कारोबारियों ने इसे खरीदकर स्टाक कर लिया। बाद में इसी भूसे के मुंहमागे दाम लिए गए। दूसरी तरफ पशु आहार भी महंगा होने से दूध उत्पादक अपने पशुओं को पर्याप्त आहार और चारा नहीं दे पाए। नतीजा यह है कि दूध का उत्पादन गिर चुका है। वर्ष 2020-21 में प्रदेश में दूध का उत्पादन लगभग 18 हजार टन रहा, लेकिन इस साल यह कम होने के आसार हैं।

पशुपालन विभाग नहीं कर पाया आकलन- पशु पालन विभाग फिलहाल इसका आकलन नहीं कर पाया है, लेकिन जानकारों का मानना है कि दूध की कमी धरातल पर दिखने लगी है। मध्यप्रदेश सहकारी दुग्ध महासंघ सांची के इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन और सागर के दुग्ध संघों के पास भी दूध का संकलन घटता जा रहा है। सभी दूध संघों को मिलाया जाए तो एक महीने में लगभग एक लाख लीटर दूध की कमी आई है। दूध के उत्पादन में कमी का कारण बढ़ते हुए तापमान को भी बताया जा रहा है, लेकिन बीते साल की तुलना में यह कमी कुछ ज्यादा ही है। दूध की कमी के बाद गांवों से दूध खरीदने के लिए अब सहकारी दुग्ध संघों और निजी कंपनियों के बीच कीमत की कूटनीति शुरू हो गई है। निजी दूध विक्रेता और कंपनियां दूध खरीदी पर किसानों को 7 और 7.25 रुपए प्रति फैट का भाव दिया जा रहा है। जबकि सांची (सहकारी दुग्ध संघ) फिलहाल 6.80 रुपए फैट का भाव ही दे रहा है। मध्यप्रदेश दुग्ध महासंघ ने प्रदेश में दूध उत्पादक किसानों को आकर्षित करने के लिए हाल ही में खरीदी दर बढ़ाई है, लेकिन इसके साथ ही उपभोक्ताओं के लिए भी दूध चार रुपए प्रति लीटर महंगा करना पड़ा।

उत्पादन गिरा तो बढ़ाएंगे खरीदी दर

इंदौर सहकारी दुग्ध संघ के अध्यक्ष मोतीसिंह पटेल का कहना है कि पशु आहार और चारा महंगा होने से किसानों के लिए दूध उत्पादन की लागत बढ़ गई है। ऐसे में हम एक बार फिर दूध की खरीदी दर बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। उधर, इंदौर दूध विक्रेता संघ के अध्यक्ष भरत मथुरावाला ने बताया कि दूध का उत्पादन गिरने का अनुमान हमने पहले ही लगा लिया था। इसीलिए इस साल हमें एक अप्रैल के बजाय एक मार्च से ही दूध की कीमतें बढ़ानी पड़ी। उत्पादन और गिरा तो हम भी खरीदी दर बढ़ाएंगे।

- दूध की कमी का असर दूध विक्रेताओं और सहकारी दुग्ध संघों को जल्दी पता चलता है। विभाग द्वारा दूध उत्पादन का आकलन पूरे साल में अलग-अलग मौसम में तीन बार किया जाता है। हमारा सर्वे जारी है। दूध उत्पादन में कमी के बारे में अभी नहीं बताया जा सकता।

  - डॉ. आरके मेहिया, संचालक, पशु पालन विभाग

- दूध के उत्पादन में कमी तो है, लेकिन यह वातावरण का भी असर है। तापमान बढ़ने के कारण भी हर साल यह स्थिति बनती है। गर्मी में लस्सी, आईस्क्रीम, दही आदि का उपयोग बढ़ जाता है। दूध की खरीदी दर हम बढ़ा चुके हैं, एक बार फिर बढ़ाई जा सकती है।

  - आरके दुरवार, महाप्रबंधक, मप्र दुग्ध महासंघ

- इस साल उत्पादन पर कुछ ज्यादा ही प्रतिकूल असर पड़ा है। दूध के बेहतर उत्पादन के लिए पशुओं की नस्ल सुधार और कृत्रिम गर्भाधान को अपनाना चाहिए।

  - डॉ. एचबीएस भदौरिया, एमडी, मप्र पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम

18 एकड़ भूमि पर अब महिला समूह लगाएंगी औषधी पौधे

» बालाघाट के परसवाड़ा में पायलट प्रोजेक्ट के तहत नवाचार

» पहले चरण में ढाई एकड़ रकबे में की जाएगी औषधी खेती

बालाघाट। औषधी और सुगंधित पौधों की खेती को लेकर विभागीय तौर पर सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत पहले चरण में करीब ढाई एकड़ रकबे में महिला समूह द्वारा खेती की जाएगी बाद में यह रकबा करीब 18 एकड़ होगा। शासन की राजस्व भूमि पर औषधी खेती को लेकर भूमि पूजन किया गया। जनपद पंचायत परसवाड़ा के अंतर्गत ग्राम पंचायत चंदना में मुख्य कार्य पालन अधिकारी जयदेव शर्मा के विशेष मार्गदर्शन और योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार मनरेगा योजना के अंतर्गत देवारण्य योजना शुरू की गई है। ग्राम पंचायत चंदना की शासकीय राजस्व भूमि में एनआरएलएम के सीएलएफ और ग्राम पंचायत के साथ संयुक्त रूप से देवारण्य योजना के अंतर्गत 6 हेक्टेयर भूमि में पौधरोपण करने के साथ ही बीच-बीच मे इंटर क्रोपिंग के साथ औषधीय पौधों की खेती करने की योजना बनाई गई है।

प्रशासकीय स्वीकृति

देवारण्य योजना में महिलाओं के स्वसहायता समूह द्वारा औषधी पौधों की खेती के लिए शासन द्वारा तकरीबन 31.44 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है, जिसमें समूह की महिलाओं ने उत्सुकता दिखाते हुए कार्य पर स्वयं उपस्थित होकर कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए भूमिपूजन किया।

-केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, भोपाल ने बनाया प्राइम मूवर, किसानों के आएंगे अच्छे दिन

सौर ऊर्जा चालित यंत्र से कम लागत में होगी उन्नत खेती

क्रांतिकारी कदमः मध्यप्रदेश के आहत किसानों को मिलेगी राहत

भोपाल। संवाददाता

किसानों की राह आसान करते हुए कृषि को लाभकारी व उन्नत बनाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, भोपाल आगे आया है। वैज्ञानिकों ने सौर ऊर्जा चालित ई-प्राइम मूवर यंत्र विकसित किया है जो कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति ला सकता है। इस यंत्र से किसान बिना ईंधन खर्च किए खेत में निराई, गुड़ाई और दवा का छिड़काव कर सकेंगे। वैज्ञानिकों ने एक वर्ष के परिश्रम के बाद इसे बनाया है। सीएनजी से चलने वाला विशेष इंजन भी बनाया है जिसे ट्रैक्टर में लगाकर खेती की लागत कम की जा सकती है।

एक घंटे में सवा एकड़ में दवा छिड़काव- सौर ऊर्जा चालित ई-प्राइम मूवर के बारे में जानकारी देते हुए वैज्ञानिकों ने बताया कि यह सौर ऊर्जा से चलित यंत्र है। इस यंत्र से किसान सिर्फ एक घंटे में सवा एकड़ जमीन में दवा का छिड़काव कर सकेंगे। इतनी ही जमीन की जुताई, निराई-गुड़ाई पांच घंटे के अंदर की जा सकेगी, जिसमें ईंधन खर्च नहीं होगा। दावा है कि ऐसा यंत्र बाजार में पहली बार आया है।

- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान ने हमेशा से ही किसानों के हित में कदम उठाए हैं। किसानों के लिए खेती लाभ का व्यवसाय बने, इसके लिए हमारे संस्थान द्वारा यह यंत्र विकसित किए गए हैं। उम्मीद है कि सौर ऊर्जा से चलने वाला ई-प्राइम मूवर कृषि के क्षेत्र में एक नई क्रांति लेकर आएगा।

  डॉ. मनोज कुमार त्रिपाठी, अध्यक्ष, प्रचार प्रसार समिति, केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, भोपाल

घर भी कर सकेंगे रोशन

इस यंत्र की बैट्री एक बार चार्ज होने के बाद तीन घंटे तक चलेगी। सौर ऊर्जा से चार्ज हुई बैटरी से किसान घर की बिजली भी जला सकेंगे। यंत्र का उपयोग अनाज को लाने-ले जाने में भी होगा। यह आसानी से दो क्विंटल तक भार ले जा सकेगा। संस्थान के प्रचार-प्रसार प्रमुख डॉ. मनोज कुमार त्रिपाठी ने बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के देश भर में 105 अभियांत्रिकी संस्थान हैं।

ट्रैक्टर के लिए सीएनजी इंजन बनाया

संस्थान के वैज्ञानिकों ने सीएनजी इंजन भी बनाया है, जिसे ट्रैक्टर में लगवाने के बाद कम खर्च में खेती के काम किए जा सकेंगे। वैज्ञानिकों ने डीजल इंजन को सीएनजी इंजन में बदला है। यह चार किलोग्राम सीएनजी में करीब एक घंटे तक ट्रैक्टर को चलाने में सक्षम बनाता है। इसे 35 हार्स पावर के इंजन में फिट किया गया है। किसान ट्रैक्टर के हार्स पावर के हिसाब से सीएनजी इंजन चुन सकते हैं। इसके उपयोग से वातावरण में बढ़ रहे प्रदूषण को रोकने में मदद मिलेगी और खेती की लागत भी घटेगी।

नियोजन से होगा जल संकट का समाधान

डॉ. सतेंद्र पाल सिंह
प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख
कृषि विज्ञान केंद्र, शिवपुरी

आज से और अभी से वर्षा जल संचय की ओर ध्यान देना होगा। इसके लिए वर्षा जल का विभिन्न स्तरों पर हर संभव नियोजन करने की जरूरत है। आम आदमी के छोटे-छोटे प्रयास भी इस दिशा में काफी सार्थक सिद्ध हो सकते हैं। जल संरक्षण की दिशा में किए गए प्रयासों से ही जल संकट का समाधान संभव होगा। इस दिशा में बातों की बजाए व्यावहारिक रूप आगे आकर काम करने की जरूरत है। इस के लिए वर्षा जल को जमीन के अंदर संरक्षित करने के साथ ही वाटर हार्वेस्टिंग तथा पानी को ताल-तलैया-तालाबों आदि में ज्यादा से ज्यादा संरक्षित करने की जरूरत है।

कहने का तात्पर्य यह है कि खेत का पानी खेत में, गांव का पानी ताल में और ताल का पानी पाताल में रोखकर संरक्षित करना होगा तभी कुछ बात बन सकेगी। देश के के अधिकांश उत्तर भारतीय राज्यों में धीरे-धीरे गर्मी अपना रौद्र रूप दिखाने लगी है। परिणाम स्वरूप पारा चढ़ना शुरू हो गया है। जैसे-जैसे सूर्यदेव का तेवर गर्म हो रहा है उसी के साथ जल संकट का दौर भी शुरू होने लगा है। देश में अलग-अलग हिस्सों में पानी की कमी की खबरें सुर्खियां बन रहीं हैं। देश के अधिकांश भागों में गर्मी शुरू होते ही हर वर्ष पानी की समस्या एक आम बात हो चली है। आखिरकार ऐसी स्थिति तब है, जब कि कुछ माह बाद वर्षा शुरू होने के बाद देश के कई हिस्सों में बाढ़ और जल प्लावन की खबरें भी सामने आती हैं। देश के कई हिस्सों में नदियां उफनकर उपना रौद्र रूप दिखाते हुए सब कुछ बहा ले जाने को आमादा होती हैं। इससे स्पष्ट तौर पर यह बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि देश में पानी की कमी की समस्या नहीं, बल्कि पानी के समुचित नियोजन की कमी है। आंकड़ों के अनुसार पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का कुल 97 प्रतिशत भाग समुद्र में खारे पानी के रूप में विद्यमान है, जो कि पेयजल एवं सिंचाई आदि के कार्य में उपयोगी नहीं है। शेष 3 प्रतिशत जल में से 2.5 प्रतिशत जल बर्फ के रूप में ग्लेशियरों-हिमखंडों एवं उनसे निकलने वाली नदियों के रूप में पाया जाता है। पृथ्वी पर मात्र आधा प्रतिशत पानी भू-गर्भ जल के रूप में जमीन में विद्यमान है। इसी मीठे जल स्रोत पर सिंचाई, पेयजल, उद्योग आदि की जवाबदारी है। यही भू-गर्भ जल मनुष्यों से लेकर जानवरों के पेयजल के साथ ही खेती में सिंचाई के काम आता है, लेकिन आज सबसे ज्यादा दोहन इसी भू-गर्भ जल का हो रहा है। जिसके चलते भू-गर्भ जल स्तर साल दर साल नीचे गिरता चला जा रहा है। देश के अधिकांश जिलों में भू-गर्भ जल की स्थिति अत्यंत भयावह है। आंकड़ों पर नजर डालें तो देश के कई विकासखंडों में भू-गर्भ जल स्तर डार्कजोन की स्थिति में आ गया है। जहां पर सिंचाई के लिए बिना शासन की अनुमति के नलकूप के लिए बोरिंग भी नहीं करा सकते हैं। देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां वर्षा की स्थिति अच्छी होने के बावजूद भी भू-गर्भ जल का स्तर 1000 फीट से लेकर 1500 फीट नीचे तक पहुंच गया है। विडंबना की बात यह है कि इस स्तर पर भी पानी की बहुतायत न होकर पानी की कमी और खारे पानी जैसी समस्याएं देखी जा रही हैं। देश के कई राज्य और उसके अधीन आने वाले जिलों में औसत वर्षा अच्छी होने के बावजूद भी जलस्तर नीचा ही नहीं, बल्कि गर्मियां शुरू होते ही पानी का संकट शुरू हो जाता है। ऐसा किस लिए है यह बात आसानी से समझी जा सकती है। यदि किसान-आम जन भू-गर्भ जल का समुचित उपयोग करने के साथ ही बारिश के जल के संचय एवं नियोजन की तरफ ध्यान दें तो इस समस्या पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। गौरतलब है कि सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता खेती में सिंचाई के लिए होती है, उसके बाद उद्योगों और पेयजल का नंबर आता है। आज जरूरत इस बात की है कि प्रत्येक स्तर पर वर्षा जल के संचय की प्रवृत्ति अपनाई जाए और वर्षा जल को संरक्षित कर आगे के लिए रखा जाए तो गर्मियों में आने वाले पानी के संकट पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। इसके लिए किसानों से लेकर आम आदमी, शासन-प्रशासन, जनप्रतिनिधि, गैर सरकारी संगठनों आदि को प्रयास करने होंगे। इस संबंध में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भी अभी कुछ दिनों पहले एक कार्यक्रम में भविष्य में आने वाले जल संकट पर गहरी चिंता व्यक्त की गई है। उनका कहना है कि जल संरक्षण की दिशा में अभी से कार्य शुरू नहीं किया गया तो बहुत देर हो जाएगी। इतना तय है कि आज से और अभी से ही इस दिशा में प्रयास नहीं किए गए तो अगला विश्वयुद्ध पानी के लिए ही होगा। भारत सरकार द्वारा इस दिशा में कई सार्थक प्रयासों पर गंभीरता से अमल किया जा रहा है। स्वंय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका महत्व समझते हुए देश में पहली बार अलग से राष्ट्रीय स्तर पर जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया है। मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री के साथ ही इस कार्य के लिए भारी भरकम बजट का प्रावधान भी सुनिश्चित किया गया है। देश की जीवन दायिनी नदियों की साफ-सफाई से लेकर नदियों को आपस में जोड़ने बात हो अथवा हर घर शुद्ध पेयजल पहुंचाने की पहल के प्रयास सभी कार्य सकारात्मक दिशा में जा रहे हैं। भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे जल शक्ति अभियान सरकार के विभिन्न मंत्रालयों का एक सहयोगी प्रयास है। भारत सरकार, राज्य सरकारें, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केन्द्र, पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा समन्वित रूप से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। जल शक्ति अभियान सरकार के विभिन्न मंत्रालयों का एक सहयोगात्मक प्रयास है। मंत्रालय ने एक राष्ट्रव्यापी अभियान 'जल शक्ति अभियान: कैच द रेन' की शुरुआत की गई है। यह अभियान 29 मार्च से 'वर्षा को पकड़ों, जहां गिरता है, जब यह गिरता है' विषय के साथ वर्षा जल को बचाने और संरक्षित करने पर केंद्रित है। यह अभियान आगामी 30 नबंबर 2022 तक देश के सभी जिलों में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में चलेगा। अभियान के तहत वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण, सभी जल निकायों की गणना, भू-टैगिंग और सूची बनाना। जल सरंक्षण के लिए वैज्ञानिक योजना तैयार करना। देश के सभी जिलों में जल शक्ति केंद्र की स्थापना करना। गहन वनरोपण ओर जागरूकता पैदा करना शामिल किया गया है। अभियान के अंतर्गत ही देश के प्रत्येक कृषि विज्ञान केंद्रों को इस अवधि के दौरान किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और किसान मेला आयोजित करने का लक्ष्य तय किया गया है। इसी प्रकार से अन्य विभागों आदि के लिए भी अलग-अलग लक्ष्य तय किए गए हैं। निश्चित रूप से भारत सरकार द्वारा इस दिशा में जिस गंभीरता से पहल की जा रही है, उसे देखते हुए यह प्रयास जल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण सिद्ध होगें। वर्षा जल संचय के साथ ही नदियों को जोड़ने के प्रयास भी भविष्य में जल संकट के समाधान की ओर एक सार्थक पहल सिद्ध होगी। भारत सरकार इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर भी रही है। केन-बेतवा जैसी नदियों को जोड़ने का कार्य हो अथवा नर्मदा-गंगा जैसी नदियों का पानी दूरदराज तक अन्य शहरों में ले जाने की बात हो, केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा इस दिशा में बहुत अच्छा काम किया गया है। नहरों से लेकर नदियों और रजवाहों पर आवश्यकता अनुसार भौगोलिक एवं पर्यावरणीय स्थितियों को ध्यान में रखकर चैक डेम का अधिक से अधिक निर्माण कराकर वर्ष पयंन्त पानी की उपलब्धता आसानी से सुरक्षित की जा सकती है। लेकिन किसानों आम नागरिकों को भी इस दिशा में आगे आकर जल संचय की प्रवृत्ति पानी को बर्बाद करने की मानसिकता में बदलाव लाने की जरूरत है। गर्मियां आते ही जल संकट के हालात बनने पर इस दिशा में बहुत चर्चा होती है। शासन-प्रशासन भी सजग दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही बरसात आ जाती है प्राथमिकता बदल जाती है और इस दिशा में प्रयास सिथिल हो जाते हैं।

फलोत्पादन से पाएं पोषण सुरक्षा

डॉ. शालिनी चक्रवर्ती
वरिष्ठ वैज्ञानिक खाद्य विज्ञान
कृषि विज्ञान केंद्र, राजगढ़

हमारे भोजन में फलों का अहम स्थान है। इनसे हमें विटामिन एवं खनिज लवणों के अतिरिक्ति प्रोटीन, वसा तथा श्वेतसार भी प्राप्त होता है। फलों का संतुलित प्रयोग करके हम पोषक तत्वों की कमी द्वारा होने वाली बीमारियों से बच सकते हैं। स्वस्थ शरीर के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 110 ग्राम फल खाने की सलाह दी गयी हं। किन्तु हमारे देश में प्रति व्यक्ति 60 ग्राम फल ही उपलब्ध हो पाता है, जो आवश्यकता से काफी कम है। इसका सेवन भी फल के मौसम तक ही सीमित होता है।

बाजार में फलों का बढ़ता मूल्य भी लोगों को फल सेवन से दूर करने में सहायक है। जब लोग कम मात्रा में अथवा असंतुलित रूप में फलों का उपयोग करते हैं, उन्हें विटामिन एवं खनिज लवणों की कमी के द्वारा होने वाली बीमारियां हो जाती हैं। निम्न आय वर्ग के लोगों में कुपोषण के कारण जन्म के समय नवजात शिशु का वजन कम होता है। उसकी मृत्यु दर अधिक होती है। लोहे की कमी के कारण खून की कमी हो जाती हैं। बालकों में विटामिन ए की कमी के कारण अंधापन हो जाता है। हमारे समाज के लगभग आठ प्रतिशत बच्चों के अंधेपन का यही कारण है। विटामिन बी समूह की कमी भी मुख्यत: निम्न आय वर्ग के लोगों में अधिक होती है। उपरोक्त कारणों से हमारा मानव संसाधन विशेषकर श्रय शक्ति बड़े पैमाने पर प्रभावित होती है। उससे हमारी राष्ट्रीय उत्पादकता प्रभावित होती है। अत: यह बहुत आवश्यक है कि लोगों को फलों की महत्ता एवं उनके पौष्टिक गुणों की जानकारी दी जाए। ताजे फलों में फास्फोरस, लोहा, सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कॉपर, क्लोरीन, कैल्शियम, पोटेशियम आदि की मात्रा उपल्बध होती है जिससे स्वस्थ्य शरीर संतुलित अवस्था में रहता है। शरीर को रोगों से लड़ने की शक्ति मिलती है। फल दूर-दराज के बागों से तुड़ाई एवं ढुलाई के उपरांत अनेक हाथों से होते हुए लगभग 3-4 दिनों बाद बाजार में उपलब्ध हो पाते हैं। इसके अतिरिक्त फलों में कीड़ों तथा बीमारियों की रोकथाम के लिए कीटनाशक रासायनों का प्रयोग किया जाता है जिसको सेहत के लिए हानिकारक माना जाता है। पूरे वर्ष ताजे फलों की उपलब्धता बनी रहे, इसके लिए घर के आस-पास की खाली पड़ी भूमि में फलदार पैधे लगाए जा सकते हैं। समाज में विभिन्न वर्ग के लोगों की आवश्यकता व रुचि अलग-अलग होती है। घर के आस पास उपलब्ध खाली भूमि गृह वाटिका का स्वरूप निर्धारित करती है। शहरों में पर्याप्त जगह न होने के कारण गृह वाटिका को कम महत्व मिल पाता हैं, परन्तु गावों में, घर, स्कूल, फार्म हाउस, विद्यालय, पंचायत भवन के आसपास यदि कृषि युक्त भूमि उपलब्ध है, तो फलोत्पान के लिए उसका प्रयोग हितकारी है। अपने आसपास किसी भी खाली पड़ी जगह को वाटिका में परिवर्तित कर आम, अमरूद, आंवला, नींबू, पपीता, अंगूर, बेल, बेर, जामुन, आदि के फलदार पौधे लगाए जा सकते हैं जिससे ताजे फलों की उपलब्धता बनी रहे। परिवार के सभी सदस्यों की पोषण तत्वों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे। वर्ष पर्यंत ताजे फलों की उपलब्धता से परिवार को समुचित पोषण प्राप्त हो सकेगा। फलोउत्पादन के नियमित कार्यों में लगे रहने से घर के सदस्यों के खाली समय का सदुपयोग हो सकेगा। घर तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर फलदार पौधे लगाने से वातावरण को प्रदूषण रहित बनाया जा सकता है।

मध्यप्रदेश में हर गरीब के सर पर होगी पक्की छत

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का संकल्प है कि प्रदेश का कोई भी गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। हर व्यक्ति का अपना पक्का मकान होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में वर्ष 2024 तक हर व्यक्ति को पक्का आवास उपलब्ध करा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री के इसी संकल्प को पूरा करने के लिए प्रदेश में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इस योजना में तेजी से कार्य जारी है और इसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 29 मार्च को प्रदेश के 5 लाख 21 हजार हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में गृह-प्रवेश कराया है। प्रदेश में अभी तक इस योजना में 24 लाख 10 हजार से अधिक आवास पूर्ण कराए जा चुके हैं। वर्ष 2016-17 में योजना में 152 आवास पूर्ण हुए थे, वर्ष 2017-18 में 6 लाख 36 हजार, वर्ष 2018-19 में 6 लाख 79 हजार, वर्ष 2019-20 में 2 लाख 71 हजार, वर्ष 2020-21 में 2 लाख 60 हजार एवं वर्ष 2021-22 में 5 लाख 41 हजार से अधिक प्रधानमंत्री आवास पूर्ण कराए जा चुके हैं। योजना के अंतर्गत प्रोजेक्ट में बैगा, सहरिया एवं भारिया जनजातियों के स्वीकृत आवासों में से 23 हजार से अधिक आवास पूर्ण कराए जा चुके हैं। भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा एक अप्रैल, 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) देश में शुरू की गई। इसमें सभी पात्र बेघर परिवारों एवं कच्चे तथा जीर्ण-शीर्ण मकानों में रह रहे परिवारों को वर्ष 2024 तक पक्का आवास उपलब्ध कराया जायेगा, जिनमें सभी बुनियादी सुविधाएं होंगी। योजना में हितग्राही का चयन सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना-2021 की सर्वे सूची के आधार पर किया जाता है। योजना में समतल क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों को 01 लाख 20 हजार प्रति आवास एवं आईपीए जिलों में 01 लाख 30 हजार प्रदान किए जाते हैं। आवास स्वीकृत होने पर 25 हजार की पहली किश्त, प्लिंथ स्तर पर 40/45 हजार की दूसरी किश्त, लिंटल स्तर पर 40/45 हजार की तीसरी किश्त तथा आवास पूर्ण होने पर 15 हजार की चौथी किश्त दी जाती है। साथ ही शौचालय निर्माण के लिए 12 हजार अतिरिक्त रूप से दिए जाते हैं। मनरेगा योजना में आवास के हितग्राही को 90 से 95 दिन की मजदूरी का भुगतान भी किया जाता है। सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना-2021 की सर्वे सूची में छूटे हुए पात्र व्यक्तियों को प्रधानमंत्री आवास दिलवाने के लिए आवास प्लस योजना शुरू की गई है। इसमें प्रदेश में छूटे हुए 31 लाख 36 हजार परिवारों का नाम जोड़ा गया है, जिन्हें भारत सरकार की गाइड-लाइन अनुसार आवास दिये जा सकेंगे। प्रदेश में अभ्युदय नवाचार के माध्यम से ऐसे ग्राम अथवा ग्राम पंचायतें, जहाँ 100 से अधिक आवास बन रहे हैं, वहां विभिन्न योजनाओं को जोड़कर एकीकृत कार्य-योजना बनाई जाती है, जिससे ग्राम एवं ग्रामीणों का सर्वांगीण विकास हो सके। इसमें सामुदायिक और व्यक्तिगत अधोसंरचना निर्माण, सामाजिक सुरक्षा, आजीविका सुदृढ़ीकरण आदि कार्य किए जाते हैं। अभ्युदय नवाचार में पूरे प्रदेश में अभी तक 2731 ग्रामों का चिन्हांकन किया गया है, जिनमें से 1668 ग्रामों के सर्वांगीण विकास की विस्तृत कार्य-योजना बनाई जा चुकी है। प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास निर्माण में फ्लाई ऐश ब्रिक्स के उपयोग के लिए हितग्राहियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ये ईंटें सामान्य ईंटों की तुलना में सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण होती है। प्रदेश में स्व-सहायता समूहों को भी आवास निर्माण के कार्य से जोड़ा गया है। प्रदेश में 33 स्व-सहायता समूहों के 300 से ज्यादा सदस्य लगभग 60 से 65 हजार फ्लाई ऐश ईट प्रतिदिन बना रहे हैं। इसके अलावा लगभग 2800 स्व-सहायता समूहों के 11 हजार 840 सदस्यों को बैंकों से ऋण दिलवा कर सेन्टरिंग सामग्री उपलब्ध कराई गई है। इन कार्यों से ग्रामीण क्षेत्र के स्व-सहायता समूहों की महिलाओं का आर्थिक सुदृढ़ीकरण भी हो रहा है।

महेंद्र सिंह सिसोदिया,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री

सीएम शिवराज सिंह चौहान बोले-किसानों सहित सभी के लिए लाभदायक है अधिकाधिक निर्यात

प्रधानमंत्री के 400 बिलियन डॉलर के निर्यात की लक्ष्य-पूर्ति में सहयोग करेंगे

मध्यप्रदेश सरकार गेहूं निर्यातकों को मुहैया कराएगी सभी सुविधाएं

› उच्च स्तरीय बैठक में निर्यातक और भारत सरकार के अधिकारी हुए शामिल

भोपाल। विशेष संवाददाता

वर्तमान में विश्व बाजार में गुणवत्ता पूर्ण गेहूं की मांग को पूरा करने के लिए राज्य सरकार निर्यातकों को सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी। मप्र का गेहूं एमपी व्हीट के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में उच्च निर्यात क्षमता के देशों जैसे इजिप्ट, टर्की, अल्जीरिया, नाइजीरिया, तंजानिया आदि के बाजारों तक भारतीय एम्बेसी के सहयोग से पहुंच बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। विभिन्न पोर्ट ट्रस्ट गेहूं के निर्यात के लिए तात्कालिक भंडारण के प्रबंध और गेहूं के जहाजों को प्राथमिकता के लिए सहमत है। निर्यातक को निर्यात की मात्रा पर भुगतान की जाने वाली मंडी फीस की प्रतिपूर्ति का कार्य मध्यप्रदेश सरकार करेगी। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्यातकों और केंद्र के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मप्र के गेहूं के अधिकाधिक निर्यात पर चर्चा के दौरान कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को लाभान्वित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। निर्यात संबंधी प्रक्रिया की अड़चनों को दूर किया जाएगा। भारत सरकार और मध्यप्रदेश सरकार के संयुक्त प्रयासों से प्रधानमंत्री के संकल्प को साकार करने का कार्य किया जाएगा।

किसानों के हित में गेहूं का निर्यात

मुख्यमंत्री ने कहा कि गेहूं का निर्यात कृषक, निर्यातकों और राष्ट्र हित में है। भारत से गेहूं और अन्य उत्पादों का निर्यात सभी के लिए लाभदायक है। रेल मंत्रालय आवश्यक रैक उपलब्ध करवाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भारत से गेहूं निर्यात बढ़ाने की मंशा से अवगत करवा चुके हैं। गत सप्ताह दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की उपस्थिति में निर्यातकों से बातचीत हो चुकी है।

मप्र का गेहूं हर कोने में पहुंचे

मुख्यमंत्री ने कहा कि मप्र के शरबती गेहूं और अन्य किस्मों की अलग पहचान है। इस वर्ष भी गेहूं का बम्पर स्टाक उत्पादन हो रहा है। मध्यप्रदेश प्रतिवर्ष 360 मीट्रिक टन गेहूं उत्पादन के साथ देश का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। गत 6 माह में गेहूं की विशेष किस्मों लोकवन,शरबती, मालवा शक्ति, सुजाता, की खरीदी किसानों से मंडियों में की गई। प्रदेश की जलवायु और यहां की मिट्टी के कारण इसे सोने के दानों जैसा गेहूं कहा जाता है। शरबती गेहूं एवं डयूरम (कठिया) गेहूं की काफी ज्यादा मांग है। प्रदेश की प्रमुख मंडियों में निर्यातकों को रियायती दर पर एक्सपोर्ट आधारित अधो-संरचना बनाने के लिए अस्थायी तौर पर भूमि और अन्य सुविधाएं देने का आकलन किया जा रहा है। इसकी गुणवत्ता और पहचान को विश्व के बाजार में स्थापित करने का यह दुर्लभ अवसर भी है। यह गोल्डन व्हीट दुनिया के हर कोने में पहुंचे और इसका नाम ही इसकी पहचान बने, इसके लिए प्रयास तेज किए गए हैं।

यह रहे मौजूद

कृषि विकास मंत्री कमल पटेल, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस,भारत सरकार के सचिव खाद्य सुधांशु पांडे, अपर मुख्य सचिव किसान-कल्याण तथा कृषि विकास अजीत केसरी, अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त शैलेंद्र सिंह ,प्रमुख सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण फैज अहमद किदवई और संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। प्रदेश के विभिन्न नगरों से अनाज व्यापारी और निर्यातक भी बैठक में शामिल हुए और सुझाव भी प्रस्तुत किए।

पीएम की मंशा निर्यात को बढ़ावा देना

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भारत से 400 बिलियन डॉलर के वाणिज्यिक निर्यात के लक्ष्य को लेकर प्रयासरत हैं। केंद्र सरकार निर्यात बढ़ाने के उपायों पर कार्य कर रही है। इस सिलसिले में निर्यात संवर्धन परिषद और संबंधित संस्थाओं के प्रयास तेज हुए हैं।

निर्यातकों को मिलेंगी सुविधाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार निर्यातकों को आवश्यक सुविधा उपलब्ध करवाएगी। राज्य सरकार की मंशा है कि मुख्य निर्यातक मध्यप्रदेश से जुड़ जाएं। भारत सरकार के सभी संबंधित मंत्रालय, रेलवे,पोर्ट ट्रस्ट, भारतीय दूतावास, गेहूं के रिकॉर्ड निर्यात के लिए प्रयासरत हैं। गेहूं निर्यात प्रोत्साहन के लिए मध्यप्रदेश के गेहूं के निर्यात पर निर्यातकों को मंडी शुल्क की वास्तविक प्रतिपूर्ति के अलावा प्रदेश में क्लीनिंग,ग्रेडिंग, सॉर्टिंग कर निर्धारित वैरायटी का गेहूं ग्रेड ए और बी के मानक अनुसार किसानों से खरीद कर निर्यात करने पर ग्रेडिंग और सॉर्टिंग में लगने वाले खर्च की निर्यातक को प्रतिपूर्ति, भंडारित अतिरिक्त गेहूं के स्टाक का प्राथमिकता से निर्यात, प्रदेश के शासकीय गोदामों को उपलब्ध करवाने पर आज की बैठक में चर्चा हुई है। इसके साथ ही प्रदेश के गेहूं के निर्यात के लिए नवीन अंतर्राष्ट्रीय बाजार विकसित करने के लिए विदेश मंत्रालय, एपीडा और मध्यप्रदेश शासन द्वारा विभिन्न देशों से समन्वय कर दीर्घकालिक व्यापार अनुबंध की कार्यवाही पर हुई चर्चा सार्थक होगी।

अशोकनगर में समर्थन मूल्य खरीदी के लिए 10 हजार ही अपात्र, 12456 किसानों के लिए भी स्लॉट बुकिंग चुनौती

गेहूं बेचने 50 फीसदी किसान नहीं करा पाए पंजीयन

अशोकनगर। संवाददाता

समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए सरकार ने इस बार इतने नियम बना दिए कि आधे किसान पंजीयन ही नहीं करा सके। कई चक्कर काटने के बाद पंजीयन कराने वाले 22 हजार 854 किसानों में से भौतिक सत्यापन करने पर 10 हजार से ज्यादा अपात्र हो गए। अब शेष बचे 12 हजार 456 किसानों को भी गेहूं बेचने के लिए ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग कराना बड़ी चुनौती रहेगी। किसानों को पंजीयन 5 फरवरी से शुरू होकर 10 मार्च तक हुआ। लेकिन पंजीयन के लिए बनाई वेबसाइट का सर्वर डाउन हो गया। बाद में इस साल बनाए गए नियमों के कारण किसानों की फजीहत हो गई। स्थिति यह रही की सोसायटी से लेकर कियोस्क सेंटरों के कई चक्कर लगाने के बाद भी पिछले साल की तुलना आधे किसान भी अपना पंजीयन नहीं करवा सके। एक माह के समयांतराल में 22 हजार 854 किसानों का ही पंजीयन हुआ। जबकि पिछले साल पंजीकृत किसानों की संख्या इससे दो गुना 42 हजार 300 से ज्यादा थी। इधर, पंजीकृत 50 प्रतिशत किसानों में से भी 40 प्रतिशत 10 हजार 398 किसान अपात्र हो गए। ऐसे में गेहूं बेचने के लिए इस अब सिर्फ 12456 किसान ही बचे हैं। इन किसानों को भी उपज बेचने के लिए पहले से ही दिन कई करते हुए स्लॉट बुक करना पड़ेगा। इसके बाद ही तय समय पर होने पर लेकर खरीदी केंद्र पर पहुंचना होगा।

पिछले साल 42 हजार ने बेचा था गेहूं

गेहूं उत्पादन की प्राथमिकता वाले जिलों में शामिल अशोकनगर जिले में पिछले साल 42300 किसानों ने समर्थन मूल्य पर सरकार को गेहूं बेचा। लेकिन इस बार पंजीयन के लिए सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल पर कहीं नए मापदंड तय कर दिए। इस कारण पिछले साल की तुलना 22 हजार 854 यानी करीब 50 फीसदी किसानों का ही पंजीयन हो सका।

34 993 हेक्टयर घटा रकबा

कुल पंजीकृत 22854 किसानों ने गेहूं का रकबा 96420 हेक्टेयर था। लेकिन भौतिक सत्यापन के बाद घटी किसानों की संख्या के साथ गेहूं का अनुमानित रकबा भी कम हो गया। सत्यापन के बाद बचे 12456 किसानों का अभी रिकॉर्ड में 61427 हेक्टेयर में लगी गेहूं की खरीदी की जाना है।

नए नियमों से फजीहत

खसरे में दर्ज नाम के दस्तावेज अनिवार्य। राजस्व रिकार्ड में दर्ज नाम से ही बैंक में खाता। बैंक खाते का आधार व मोबाइल नंबर से भी लिंक होना जरूरी। सब होने के बाद मोबाइल पर आए ओटीपी से ही पंजीयन।

फायदा उठाएंगे व्यापारी

सरकारी नियमों के कारण पंजीयन में उलझे किसानों की मजबूरी का फायदा इस बार व्यापारी उठाएंगे। सरकारी सिस्टम के कारण पंजीयन नहीं करा पाए किसानों के सामने अब गेहूं बेचने की समस्या रहेगी। यह किसान अब चाहकर भी समर्थन मूल्य पर गेहूं नहीं बेच सकेंगे। इन किसानों को अब निजी व्यापारियों को ही ओने पौने दामों पर अपनी उपज बेचना पड़ेगी। सारी समस्याओं से निपटते हुए सरकारी पैमाने पर खरे साबित हुए जिले के 12456 किसानों के सामने अब स्लॉट बुकिंग कराने की नई चुनौती खड़ी है।

जिले में 4 अप्रैल से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी शुरू हो जाएगी। खरीदी करने वाली सोसायटी सहित स्व सहायता समूह सदस्यों को प्रशिक्षित कर दिया है। पंजीकृत किसानों को ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग कराना होगा।

रवि मालवीय, डिप्टी कलेक्टर व नोडल अधिकारी खाद्य आपूर्ति

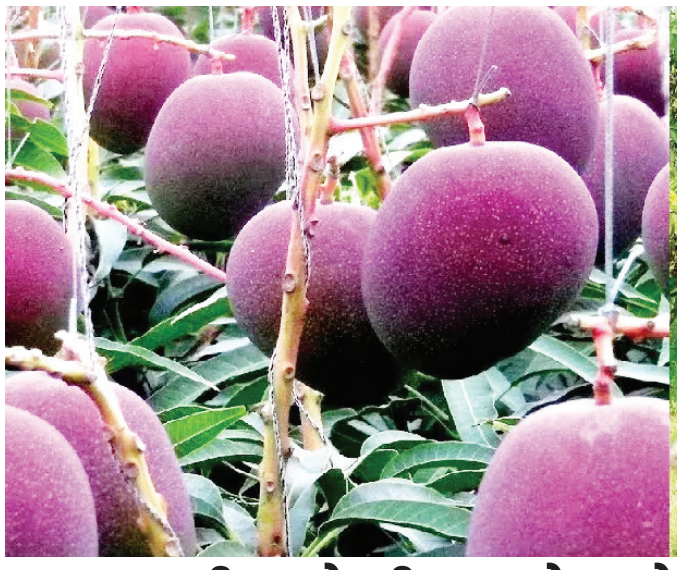

तीन चौकीदार और नौ कुत्ते दे रहे पहरा

जबलपुर के बगीचे में जापानी आम कीमत 2.7 लाख रुपए किलो

जबलपुर। संवाददाता

हमारे देश के हर राज्य में अलग-अलग किस्म के आम की खेती भी की जाती है। जिनकी कीमत भी ज्यादा होती है।

सबसे पसंदीदा फल होने के कारण यहां अच्छे किस्म के आमों के सेवन के लिए लोग अच्छी खासी रकम भी खर्च करने को तैयार रहते हैं। यही वजह है कि देश में अलग-अलग तरह की आम के किस्मों की खेती भी की जाती है। लेकिन आज हम जिस आम के बारे बताने जा रहे हैं उसकी कीमत जानकर आप चौंक जाएंगे। जबलपुर में चरगवां रोड पर संकल्प परिहार और रानी परिहार के बगीचे में आम के एक ऐसी किस्म उगाई जाती है। आम का नाम है टाइयो नो टमैंगो जिसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 2 लाख 70 हजार रुपए किलो बताई जाती है। इसकी खेती आमतौर से जापान में होती है।

सुरक्षा में लगे गार्ड और कुत्ते- टाइयो नो टमैंगो नाम के इस आम की कीमत ज्यादा होने की वजह से इसकी सुरक्षा का भी खास इंतजाम किया गया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाले संकल्प परिहार ने इन आमों की सुरक्षा के लिए अपने बगीचे में 3 गार्ड और 9 कुत्ते लगा रखे हैं।

कहा जाता है सूर्य का अंडा

संकल्प परिहार बताते हैं कि इस आम को एग ऑफ सन यानी सूर्य का अंडा भी कहा जाता है। ये आम पिछले कुछ सालों में काफी चर्चा में रहा है। दरअसल, यह अपनी कीमत की वजह से लोगों की नजर में बना हुआ था। कुछ वक्त बाद बगीचे से कुछ आम की चोरी भी हो गई। ऐसे में उन्हें आमों की सुरक्षा के इंतजाम करने पड़े। इसके लिए उन्हें अतिरिक्त पैसे भी खर्च करने पड़ रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ये आम जब पूरी तरह से पक जाता है तो इसका वजन 900 ग्राम तक पहुंच जाता है। साथ ही इसका रंग हल्का लाल और पीला हो जाता है। इसकी मिठास भी सबको अपनी तरफ आकर्षित करती है। इसके अलावा इसमें अन्य आमों के मुकाबले रेशे बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं।

उगाना बड़ी चुनौती

रानी परिहार कहती हैं कि इस आम को उगाना किसी चुनौती से कम नहीं है क्योंकि इसमें बहुत कम फल आते हैं और भारत में इनका अच्छा दाम ही नहीं मिलता, लेकिन उन्होंने शौकिया तौर पर इस आम को उगाया था और वे सफल रहीं। जापान में इस आम को पॉली हाउस के भीतर उगाया जाता है। लेकिन भारत में इसे खुले वातावरण में भी उगाया जा सकता है।

बंजर जमीन पर उगाया

रानी परिहार का कहना है कि अपनी बंजर पड़ी जमीन पर इसे खुले वातावरण में उगाया है। शुरुआत में 4 एकड़ के बगीचे में उन्होंने आम के कुछ पेड़ लगाए थे। अब उनके बगीचे में 14 हाइब्रिड तथा छह विदेशी किस्म के आम हैं। फिलहाल उन्होंने अपने 4 एकड़ के बगीचे में 14 अलग-अलग किस्म के आमों को लगा रखा है। इसके अलावा उन्होंने टाइयो नो टमैंगो के भी 52 पेड़ भी लगाए हुए हैं।

जापानी वैरायटी के बगीचे में कई आम

रानी परिहार का कहना है कि यह बहुत ही स्वादिष्ट आम है। इसमें बिल्कुल भी रेशे नहीं पाए जाते और स्वाद इतना लजीज होता है कि खाने वाला कभी भूलता नहीं है। जापानी वैरायटी के भी रानी के बगीचे में कई आम हैं। इनमें स्वर्ग बैगनी और पिंक आम भी है। इस बगीचे में मैंगो 2जी नाम का भी एक आम है। जिसका पकने पर कुल वजन 2 किलो के लगभग होता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आम की देसी और विदेशी सभी किस्म के फल खुले वातावरण में पैदा हो रहे हैं।

मध्यप्रदेश में मिला 20 करोड़ रुपए का क्लेम

पशुपालकों के लिए सुरक्षा कवच बनी 'पशुधन बीमा'

भोपाल। संवाददाता

किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए अब राज्य सरकारें सिर्फ फसलों पर निर्भर नहीं हैं, बल्कि इसके लिए वो पशुपालन और मछली पालन पर भी फोकस कर रही हैं। पशुपालन करने वाले किसानों को पशुओं की बीमारियों के रूप में एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा बाढ़, चक्रवात एवं अकाल जैसे हालात में पशुओं की मौत से नुकसान की आशंका रहती है। मध्य प्रदेश के पशुपालन एवं डेयरी विकास मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने बताया कि पशुधन बीमा योजना में लाभार्थियों को अब तक 20 करोड़ 21 लाख 41 हजार रुपए की क्लेम रकम का भुगतान किया जा चुका ह। जबकि पिछले 3 साल में बीमा कंपनी को उन्होंने 6 करोड़ 94 लाख 94 हजार का प्रीमियन भुगतान किया था। योजना में दुधारू पशु सहित अन्य मवेशी भी शामिल है। यह योजना प्रदेश के सभी जिलों में लागू है। एक लाभार्थी के अधिकतम 5 पशुओं का बीमा प्रीमियन अनुदान पर किया जाता है। अब तक 48 हजार 200 पशुओं का बीमा किया जा चुका है। यह बीमा योजना पशुपालकों के लिए सुरक्षा कवच बनकर उभर रही है।

किन पशुओं का होता है बीमा

पटेल ने बताया कि योजना का उद्देश्य पशुपालकों को उनके पशुओं के लिए बीमा सुविधा प्रदान कर पशुओं की मृत्यु से होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति करना और होने वाली आर्थिक हानि को रोकना है। योजना में सभी प्रकार के पशुओं-दुधारू, देशी-संकर गाय, भैंस अन्य पशु जैसे घोड़ा-गधा,भेड़-बकरी, सूअर, खरगोश, भैंस आदि का बीमा किया जाता है।

कब कितने पशुओं का बीमा

योजना में गरीबी रेखा के ऊपर वाले लाभार्थियों का 50 प्रतिशत अनुदान पर प्रीमियम बीमा किया जाता है। इसमें केंद्र अंश और राज्य अंश 25.25 प्रतिशत शामिल है। वहीं अनुसूचित जाति जनजाति गरीबी रेखा से नीचे वाले लाभार्थियों का 70 प्रतिशत अनुदान पर प्रीमियम बीमा किया जाता है। इसमें केंद्र अंश 40 प्रतिशत और राज्य अंश 30 प्रतिशत शामिल है। योजना में वर्ष 2014-15 में 11168, वर्ष 2015-16 में 37486, 2016-17 में 59113, 2017-18 में 38219, वर्ष 2018-19 में 52908 और 2019-20 में 52704 पशुओं का बीमा किया गया।

इन दस्तावेजों की होगी जरूरत

यदि पशुपालक अपने पशुओं का बीमा करवाना है, तो पशुपालन करने वाले व्यक्ति का आधार कार्ड,एपीएल, बीपीएल कार्ड, पशु से संबंधी विवरण, निवास प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, बैंक पासबुक एवं पहचान पत्र देना होगा। 20वीं पशुगणना के मुताबिक मध्य प्रदेश प्रदेश में 40.6 मिलियन पशुधन हैं। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि पशुपालन के बिना कृषि संभव नहीं है। इसलिए राज्य सरकार पशुपालन पर फोकस कर रही है।

कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने किया तालाब जीर्णोद्धार कार्य का शुभारंभ और कहा

शिवपुरी को भविष्य में जल संकट से बचने जल संरक्षण जरूरी

खेमराज मौर्य। शिवपुरी

अभी जलाभिषेक अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत तालाबों का जीर्णोद्धार का काम शुरू किया गया है। कोलारस की ग्राम पंचायत निवोदा में कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी के मुख्य आतिथ्य में तालाब जीर्णोद्धार कार्य का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल, किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष चीमा सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे। कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने कहा कि पौधरोपण और जल संरक्षण में शुरू से ही मेरी रुचि रही है। यदि हम देखें तो कुछ वर्षों पूर्व पानी की इतनी समस्या नहीं थी, लेकिन अब धीरे-धीरे जल स्तर नीचे जा रहा है। तालाब सूख रहे हैं। आगे भविष्य में हमें गंभीर परिस्थितियों का सामना ना करना पड़े इसके लिए जल संरक्षण और भू-जल संवर्धन बहुत जरूरी है। इसके लिए जलाभिषेक अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत तालाबों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। सभी नागरिक जागरूक रहें और जहां कहीं तालाब निर्मित किए जा सकते हैं उसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को उपलब्ध कराएं। उन्होंने सिंध नदी और कूनो नदी पर बनने वाले डैम के संबंध में जानकारी दी कि शिवपुरी में जल की समस्या को दूर करने के लिए उनके द्वारा लगातार प्रयास जारी हैं। कार्यक्रम में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने भी ग्रामीणों से कहा कि यदि हमें भविष्य में जल संकट का सामना करने से बचना है तो अभी से जल संरक्षण की दिशा में काम करना होगा।

बालिकाओं ने निकाली कलश यात्रा

कार्यक्रम की शुरुआत कन्या पूजन कर की गई। बालिकाओं और महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। अधिकारियों ने भी श्रमदान किया और तालाब जीर्णोद्धार कार्य का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक वीरेंद्र रघुवंशीए कलेक्टर अक्षय कुमार सिंहए पुलिस अधीक्षक और अन्य जनप्रतिनिधियों ने पौधरोपण किया।

प्रचार रथ को दिखाई हरी झंडी

जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल पहुंचाने का अभियान जारी है। शिवपुरी जिले में भी लगभग 800 गांव को इस अभियान से जोड़ा जाएगा। जल जीवन मिशन के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह जागरूकता रथ गांव गांव जाकर जल जीवन मिशन के बारे में और इसके संचालन के बारे में ग्रामीणों को जानकारी देगा।

दो हेक्टेयर में मिर्ची की खेती से अलापुरा के किसान ने कमाए 18 लाख

'मिर्ची' रुलाती ही नहीं, हंसाती भी है...

प्राइवेट कंपनियों की नौकरी छोड़ शिवचरण ने पिछले साल से शुरू की मिर्ची की खेती

श्योपुर। संवाददाता

तीखी मिर्ची खाने से अक्सर आंखों से आंसू निकल आते हैं। मिर्ची के हाथ यदि आंख में लग जाए तो भी आंखों से आंसू आ जाते हैं। मगर मिर्ची रुलाती ही नहीं, बल्कि हंसाती भी है। सुनने में यह बात कुछ अटपटी जरूर लग रही होगी, मगर है सच। इसकी बानगी अलापुरा में देखी जा सकती है, जहां मिर्ची की पैदावार एक किसान को हंसा रही है, क्योंकि मिर्ची की खेती से किसान को लाखों की आमदनी प्राप्त हो रही है।

बड़ौदा तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम अलापुरा निवासी युवा किसान शिवचरण नागर अपने गांव के ऐसे इकलौते किसान हैं, जो 2 हेक्टेयर में मिर्ची की खेती कर रहे हैं। परपंरागत खेती में बदलाव करने वाले किसान शिवचरण नागर बताते हैं कि उन्हें दो हेक्टेयर में हुई मिर्ची की पैदावार से 18 लाख 2 हजार की आमदनी हुई है। इतनी आमदनी सोयाबीन और गेहूं की परंपरागत खेती से होना संभव नहीं है। यहां बता दें कि अलापुरा निवासी शिवचरण नागर एमए तक पढ़े हैं और अब तक कई प्राइवेट कंपनियों में नौकरी कर चुके हैं। सरकारी नौकरी में जाने के लिए भी उन्होंने प्रयास किए, मगर सफल नहीं हुए। अब उन्होंने प्राइवेट कंपनियों की नौकरी छोड़कर अपने गांव लौटकर खेती करना शुरू कर दिया। अन्य किसानों की तरह वे भी खरीफ में सोयाबीन और धान तथा रबी सीजन में गेहूं और चने की खेती करते थे। दो हेक्टेयर खेत में सोयाबीन और गेहूं की पैदावार से उन्हें डेढ़ से दो लाख की आय हुई। जबकि मेहनत भी काफी अधिक लगी। पिछले साल किसान शिवचरण नागर कृषि विभाग की आत्मा योजना के अन्तर्गत अधिकारियों के संपर्क में आए और उनके बुलावे पर प्रशिक्षण में भी शामिल हुए। इसके बाद उन्होंने शिवपुरी सहित पड़ोसी प्रांत राजस्थान के जिलों में जाकर मिर्ची की फसल के बारे में वहां के किसानों से जानकारी हांसिल की और मिर्ची फसल उत्पादन की तकनीक पर गहन अध्ययन किया।

लाभ का धंधा

02 हेक्टेयर में की बोवनी

1400 क्विंटल मिला उत्पादन

2000 रुपए क्विंटल मिला भाव

28 लाख में बिकी मिर्ची

9.8 लाख रुपए आई लागत

दो हेक्टेयर में 1400 क्विंटल मिर्ची का उत्पादन

मिर्ची फसल उत्पादन की तकनीक पर गहन अध्ययन करने के बाद किसान शिवचरण नागर ने गत जुलाई माह में अपने एक हेक्टेयर खेत में मिर्ची की फसल उगाई। फिर एक माह बाद एक हेक्टेयर में मिर्ची की फसल ओर लगा दी। किसान शिवचरण नागर बताते है कि उन्होंने 2 हेक्टेयर में तनवी कलस्की और सिंजेण्टा किस्म की मिर्ची की फसल तैयार की। इससे उन्हें 1400 क्विंटल मिर्ची का उत्पादन हुआ, जो 2 हजार रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से मंडी में बिकने पर उन्हें 28 लाख रुपए प्राप्त हुए। जबकि इसमें खेती की तैयारी, उर्वरक, दवा, सिंचाई तथा मजदूरी, भाडा और लोडिंग आदि पर 9 लाख 8 हजार रुपए की लागत आई। इस तरह उन्हें दो हेक्टेयर में तैयार की मिर्ची से 18 लाख 2 हजार रुपए की आमदनी हुई।

दूसरे किसानों को भी दे रहे प्रेरणा

किसान शिवचरण बताते हैं कि अभी तक वे मिर्ची की फसल को श्योपुर मंडी में विक्रय के लिए भेज रहे थे, लेकिन अब वे राजस्थान की बारां मंडी में मिर्ची को विक्रय के लिए पहुंचा रहे है, क्योंकि बारां मंडी में श्योपुर मंडी से अधिक भाव मिल रहा है। वे दूसरे किसानों को भी मिर्ची की खेती के लिए प्रेरित कर रहे है। उनका कहना है कि जितनी आय मिर्ची की खेती से हो रही है, उतनी आय अन्य फसलों से होना संभव नहीं है।

-मधुमक्खी पालन से मालामाल होंगे किसान, -वैज्ञानिक तरीके से उत्पादन बढ़ाने पर जोर

दूध की तरह विकसित होगा शहद उद्योग

भोपाल/नई दिल्ली। संवाददाता

भारत में मौजूदा समय में भी देश के अंदर मधुमक्खी पालन बड़े स्तर पर शहद का निर्यात भी किया जा रहा है, लेकिन देश के शहद को एक सशक्त पहचान नहीं मिल पाई है। इससे शहद उत्पादित करने वाले किसानों को भी फायदा नहीं मिल पाता है। हालांकि अब इसके लिए प्रयास शुरू होने लगे हैं। जिसके तहत देश का डेयरी कॉपरेटिव नेटवर्क देश के शहद को नए पंख लगाने जा रहा है। जिसमें शहद को दूध की तरह ही स्वतंत्र उद्यम के तौर पर विकसित करने की योजना है। मधुमक्खी पालन का जिक्र वेद और पुराणों में भी मिलता है।

500 करोड़ की योजना का ऐलान- मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर पैकेज में भी वित्त मंत्री ने 500 करोड़ की योजना का ऐलान किया था। इसके अलावा कई राज्यों द्वारा इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए सब्सिडी भी दी जाती है। किसानों के लिए ये व्यापार फायदे का सौदा इसलिए भी है, क्योंकि इसकी शुरुआत के लिए ज्यादा पैसे नहीं लगाने पड़ते हैं।

सेमिनार का आयोजन किया गया- नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, एनडीडीबी और नेशनल बी बोर्ड एनबीबी की तरफसे राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन के तहत एक ऑनलाइन सेमिनार का आयोजन किया गया। इस दौरान एनडीडीबी के अध्यक्ष मीनेश शाह ने कहा कि मधुमक्खी पालन को देश में एक स्वतंत्र उद्यम के तौर पर विकसित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के डेयरी नेटवर्क को देखते शहद को स्वीट क्रांति के तौर पर बढ़ाने का आह्वान किया था। उसी क्रम में हम डेयरी नेटवर्क के प्रयोग करते हुए वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं।

मीठे की जरूरतों को पूरी करेगा शहद - दुनियाभर में बढ़ती बीमारियों के बाद से दुनिया के कई देशों में कृत्रिटम मिठास की जगह प्राकृतिक मिठास की चाहत बढ़ी है। इसके तहत ब्रिकटेन समेत कई देशों के लोग अपनी शरीर के मीठे की जरूरतों को पूरा करने के लिए शहद का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं कई कंपनियां शहद से बने खाद्य प्रदार्थों को बढ़ावा दे रही हैं।

डेयरी कॉपरेटिव के पास वैल्यू चैन

एनडीडीबी के अध्यक्ष मीनेश शाह ने कहा कि किसानों तक पहुंच होने की वजह से देश के डेयरी कॉपरेटिव मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने में एक सक्षम माध्यम है। उन्होंने कहा कि हम किसान और मधुमक्खी पालकों को संगठित करके एक किसान उत्पादक संगठन के लिए भी काम कर रहे हैं। डेयरी कॉपरेटिव के पास एक स्थापित वैल्यू चैन है, जिसमें दूध की खरीद, प्रंसस्करण और विपणन शामिल है। यह चैन शहद के लिए भी कामयाब हो सकती है। किसान वैज्ञानिक तरीके से शहद का अधिक से अधिक उत्पादन कम से कम मूल्य में करेंए इसके लिए किसानों को प्रोत्साहित करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि मधुमक्खी पालन कृषि और बागवानी फसलों का उत्पादन बढ़ाने में भी सहायक है।

किसानों की बढ़ेगी आमदनी

एनडीडीबी अध्यक्ष मीनेश शाह ने कहा कि मधुमक्खी पालन में स्वरोजगार और किसानों को अतिरिक्त आय देने की अच्छी संभावना है। उन्होंने कहा कि एनडीडीबी ने वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए देश भर में किसानों को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है। जिसमें केवीके और डेयरी कॉपरेटिव नेटवर्क का सहयोग लिया जा रहा है। एनडीडीबी 40 प्रशिक्षण कार्यक्रम कर चुका हैं, जिसमें 1100 किसानों ने हिस्सा लिया था।

देशभर में 55 किसान उत्पादक संगठन

सम्मेलन में नेशनल बी बोर्ड के कार्यकारी निदेशक एनके पाटले ने बताया कि यह सम्मेलन शहद के अलावा मधुमक्खी पालन के दौरान उत्पादित होने वाले अन्य उत्पादों के बारे में जानकारी देने के लिए है। जिसमें वैक्श प्रमुख है। उन्होंने कहा कि मौजूद समय में मधुमक्खी के वैक्श की मांग फार्माज के साथ ही कॉस्मेटिक उद्योग में बढ़ी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि बोर्ड मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए देशभर में 100 किसान उत्पादक संगठन बना रहा है। जिसमें से 55 बनाए जा चुके हैं। वहीं उन्होंने बताया कि देशभर में 3 शहद परीक्षण केंद्र भी बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही मधुमक्खी ब्रीडिंग सेंटर भी बनाए जा रहे हैं।

नैनो यूरिया से बेहतर फसल उत्पादकता

-भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का दावा

भोपाल/नई दिल्ली। संवाददाता

नैनो यूरिया से बेहतर फसल उत्पादकता- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का दावा-कृषि विभाग (डीए एंड एफडब्ल्यू) ने उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 में नैनो यूरिया को नैनो नाइट्रोजन उर्वरक के रूप में अस्थायी रूप से अधिसूचित किया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) केवीके (कृषि विज्ञान केंद्र) द्वारा भारत भर में किए गए 94 फसलों में 11000 क्षेत्र परीक्षणों के अनुसार, नैनो यूरिया के उपयोग से फसल उत्पादकता में सुधार होता है, भगवंत खुबा, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में इसका हवाला दिया। नंगल (पंजाब) और ट्रॉम्बे (महाराष्ट्र) में नैनो यूरिया संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए दो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) अर्थात् नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल) और राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक लिमिटेड (आरसीएफ) ने भी इफको के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। विभाग ने तरल उर्वरकों के ड्रोन छिड़काव के लिए उद्यमियों के विकास के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। नैनो यूरिया के उपयोग को विभिन्न गतिविधियों जैसे जागरूकता शिविर, वेबिनार, स्ट्रीट शो, फील्ड प्रदर्शन, किसान सभा और क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्मों आदि के माध्यम से बढ़ावा दिया जाता है।

प्रदेश में खल रही किसानों को कमी, आवेदन लेने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पाई प्रक्रिया

दो साल बाद भी नहीं हो सकी किसान मित्र की भर्ती

» नाथ सरकार ने एक साथ 28 हजार किसान मित्रों को किया था बर्खास्त

» मप्र में सिर्फ 50 फीसदी किसान ही करा पा रहे मृदा परीक्षण

भोपाल। विशेष संवाददाता

राज्य सरकार के तमाम प्रयासों के बाद भी खेती लाभ का धंधा नहीं बन पा रही है। हर साल किसान उत्पादन बढ़ाने के लिए लाखों रुपए रसायनिक खाद पर खर्च कर रहा है। मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाने के लिए भी अलग से खाद डाली जा रही है। बीज की किस्म बदलने का प्रयोग भी लगातार जारी है। इन सबके बावजूद किसानों को अपेक्षाकृत पैदावार नहीं मिल पा रही है। इन सबमें किसानों को अतिरिक्त पैसे भी खर्च करने पड़ रहे हैं। यह स्थिति तब है जब पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के गृह जिले गुना में एक नहीं, बल्कि तीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला हैं। इसके बाद भी वर्तमान में 50 फीसदी से कम किसान ही मिट्टी परीक्षण करा रहे हैं। हालांकि, जिन किसानों के पास मृदा स्वास्थ्य कार्ड मौजूद हैं, वे इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। इस तरह सरकार की अहम योजना का लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा है।

राज्य सरकार ने ने मृदा परीक्षण के प्रति किसानों को जागरूक करने ग्रामीण स्तर पर किसान मित्र भी पदस्थ किए थे, लेकिन कमलनाथ सरकार ने 15 माह के कार्यकाल में 28 हजार किसान मित्रों की सेवा समाप्त कर दी थी। हालांकि, शिवराज सरकार बनते ही कृषि मंत्री कमल पटेल ने किसान मित्रों की तैनाती की घोषणा की थी, लेकिन आज तक अमल नहीं हो पाया। सालभर पहले किसानों से आवेदन भी लिए गए थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ, जबकि दक्ष किसान मित्र सरकार के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। गौरतलब है कि एक किसान मित्र के जिम्मे दो गांव होते हैं, जो किसानों को जागरूक करने का काम करते हैं। प्रदेश में अभी 30 हजार के करीब किसान मित्रों की जरूरत है। चौंकाने वाली बात यह है कि सरकार किसान मित्रों को सिर्फ 12 हजार रुपए सालाना वेतन देती थी। हालांकि, कई बार मांग के बाद वेतन बढ़ाने का आश्वासन दिया गया, लेकिन जब भर्ती ही नहीं हो रही, तो वेतन बढ़ाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। किसान मित्रों की कमी के कारण वर्तमान में प्रदेश में मृदा परीक्षण कराने वाले किसानों की संख्या मुश्किल से 50 प्रतिशत तक पहुंच सकी है।

» गुना में तीन मृदा परीक्षण प्रयोगशाला फिर भी जांच कराने वाले किसान नाम मात्र के

» पंचायत मंत्री के जिले में मृदा परीक्षण रिपोर्ट किसानों के बचा सकती है लाखों रुपए

» जनजागरुकता के अभाव में अधिकांश किसान आज भी योजना के लाभ से वंचित

» किस भूमि को कितनी उर्वरक की जरूरत किसान को नहीं पता, अंदाज से डालते हैं खाद

बगैर जरूरत डाल रहे उर्वरक

किसान व कृषि विभाग के अधिकारियों से चर्चा करने पर सामने आया है कि वर्तमान में ऐसे किसानों की संख्या बहुत अधिक है, जिन्हें मृदा परीक्षण के फायदे के बारे में जानकारी नहीं है। यही वजह है कि ऐसे किसान दूसरों की देखा देखी ऐसे उर्वरक का इस्तेमाल अपनी उपज बढ़ाने में कर रहे हैं जिसकी जरुरत न तो उस फसल को है और न ही उस खेत की मिट्टी को। इस तरह जानकारी के अभाव में किसान अपना फायदा करने के बजाए नुकसान ही कर रहा है। जिसका सबसे बड़ा परिणाम बीते तीन चार सालों में सोयाबीन की पैदावार में हुआ नुकसान है।

मिट्टी का हेल्थ कार्ड बनवाना जरूरी

कृषि वैज्ञानिक के अनुसार वर्तमान में अच्छी पैदावार के लिए मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में किसानों को अपने खेतों की मिट्टी का परीक्षण कर हेल्थ कार्ड बनवाना जरूरी है। क्योंकि इसी रिपोर्ट से तय होता है कि किस खेत की मिट्टी में कौनसे पोषक तत्व की कमी है तथा नहीं है। इसके आधार पर ही निष्कर्ष निकलता है कि कौनसी फसल इसमें सही रहेगी। इसके अलावा फसल में कौनसा उर्वरक और कितनी मात्रा में उपयोग किया जाना है, यह भी मिट्टी के हेल्थ कार्ड पर ही निर्भर रहता है। यदि किसान हेल्थ कार्ड के हिसाब से खेती करता है तो उसे फसल उत्पादन पर खर्च होने वाले कुल बजट में 20 से 25 प्रतिशत राशि की बचत होगी। साथ ही फसल उत्पादन की दर भी बढ़ेगी, जिससे उसे अच्छा भाव मिल सकेगा।

कब कराएं परीक्षण

एक मृदा परीक्षण प्रयोगशाला के प्रमुख ने बताया कि वर्तमान में जिस तरह से किसान दो बार फसल ले रहे हैं। साथ ही सब्जी की खेती भी कर रहे हैं। ऐसे में उसे हर साल मृदा परीक्षण कराना चाहिए। जिससे यह पता चल सकेगा कि कौन से खेत की मिट्टी में लगातार फसल लेने से किन पोषक तत्वों की कमी आई है, जिसे पूरा करने किस उर्वरक की कितनी जरूरत होगी। साथ ही उस खेत में फसल चक्र के तहत कौनसी फसल की पैदावार अनुकूल होगी।

डीएपी को प्रचलन बनाया किसानों ने

कृषि विशेषज्ञों की मानें तो किसानों में इस समय बेहद जारुकता की कमी है। वह अपने पड़ोसी किसान की देखादेखी खेती करने में लगा है। विभाग के तकनीकी जानकार जब उसे सही जानकारी देते हैं तो उसे वह हल्के में लेता है। कई किसानों से चर्चा करने पर सामने आया है कि दलहनी फसलों में यूरिया जरूरी नहीं होता। तेल वाली फसल में सल्फर की जरूरत होती है। सरसों की फसल में डीएपी की जरूरत नहीं होती, बल्कि सुपरफास्ट की आवश्यकता होती है। लेकिन फिर भी किसानों ने डीएपी खाद का उपयोग प्रचलन बना लिया है। यही कारण है कि सीजन के समय किसान खाद के लिए लंबी-लंबी लाइनों में लगे नजर आते हैं।

-पन्ना, सतना, छतरपुर, अलीराजपुर में परेशानी, -बुरहानपुर के हर घर में नल से पहुंचा पेयजल

प्रदेश के 60 फीसदी घर नल-जल से वंचित

भोपाल। संवाददाता

गर्मी के दिनों में मध्यप्रदेश के अधिकांश जिलों में जलसंकट पैदा हो जाता है। दूरस्थ ही नहीं, बल्कि बड़े शहरों में भी पीने के पानी का संकट लोगों को परेशान करने लगता है। हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी प्रदेश में जलसंकट बरकरार है। प्रदेश में 60 फीसदी आबादी के पास नल-जल की सुविधा नही है। गर्मियों के दिनों में इन्हें पीने के पानी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। प्रदेश के 1 करोड़ 22 लाख 27 हजार परिवारों में 39.48 प्रतिशत यानी 48,27,386 फैमिली के पास ही ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई (नल जल की सुविधा) है। बुरहानपुर प्रदेश का एक मात्र ऐसा जिला है, जहां नल से जल की सप्लाई हो रही है। जल जीवन मिशन की रिपोर्ट के मुताबिक बुरहानपुर जिले के सभी 1,01,905 परिवारों के पास नल-जल की सुविधा उपलब्ध है। प्रत्येक परिवार को घरेलू नल जल कनेक्शन दिया जा चुका है। जलप्रदाय किया जा रहा है। योजनाओं के संधारण के लिए ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति बनाई गई हैं। फिलहाल 60 से 100 रुपए प्रतिमाह जल दर (टैक्स) की लिया जा रहा है।

पानी की सुविधा में टॉप-5 जिले

जिला	कुल परिवार	नल-जल	परिवारों का प्रतिशत
बुरहानपुर	101905	101905	100 प्रतिशत
इंदौर	194870	160203	82.21 प्रतिशत
बालाघाट	360466	218605	60.65 प्रतिशत
नरसिंहपुर	231348	131698	56.93 प्रतिशत
खंडवा	242645	137825	56.80 प्रतिशत

बुंदेलखंड पैकेज जहां खर्च हुआ, वही जिले सूखे

साल 2008-09 केंद्र सरकार द्वारा बुंदेलखंड पैकेज के तहत साढ़े तीन हजार करोड़ रुपए का फंड दिया गया था। इस पैकेज से बुंदेलखंड का सूखा दूर करने के लिए करीब 1298 संरचनाएं बनाई गई थी। इनमें से 1098 संरचनाएं अनुपयोगी पाई गई थीं। इसके बावजूद पन्ना, छतरपुर जिलों में सबसे ज्यादा परिवार वाटर सप्लाई से वंचित हैं। पन्ना जिले में महज 13.82 फीसदी और छतरपुर जिले में 20.81 फीसदी परिवारों के पास नल का जल पहुंच पा रहा है। नल-जल सुविधा के मामले में सबसे कम फैमिली कवरेज वाले जिलों में पन्ना (13.82 फीसदी), सतना(18.82 फीसदी), छतरपुर(20.81फीसदी), अलीराजपुर(23.32 फीसदी) की हालत सबसे खराब है।

इन जिलों में आधे परिवारों के पास नल-जल सप्लाई की सुविधा नहीं

49 से 40 फीसदी नल- जल सुविधा वाले परिवार में नीमच,रतलाम, बड़वानी, मंदसौर, भोपाल, सीहोर, उमरिया, देवास, आगर, श्योपुर, मुरैना, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, राजगढ़ जिला शामिल है।
39 से 25 फीसदी नल- जल सुविधा वाले परिवार में विदिशा, कटनी, सिवनी, ग्वालियर, मंडला, उज्जैन, अनूपपुर, शाजापुर, रायसेन, जबलपुर, गुना, झाबुआ, डिंडोरी, अशोकनगर, शहडोल, दमोह, रीवा, सीधी, शिवपुरी, सागर, भिंड, टीकमगढ़, सिंगरौली जिला शामिल है।

आवश्यकता

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर और मुरैना से प्रकाशित

जागत गांव हमार

कृषि और पंचायत पर आधारित साप्ताहिक समाचार पत्र के लिए जिला, जनपद स्तर पर संवाददाता चाहिए।

संपर्क करें

जबलपुर, प्रवीण नामदेव-9300034195
शहडोल, राम नरेश वर्मा-9131886277
नरसिंहपुर, प्रहलाद कौरव-9926569304
विदिशा, अवधेश दुबे- 9425148554
सागर, अनिल दुबे-9826021098
राहतगढ़, भगवान सिंह प्रजापति-9826948827
दमोह, बंटी शर्मा -9131821040
टीकमगढ़, नीरज जैन -9893583522
राजगढ़, गजराज सिंह मीणा -9981462162
बैतूल, सतीष साहू-8982777449
मुरैना, अवधेश दण्डोतिया -9425128418
शिवपुरी, खेमराज मौर्य-9425762414
भिण्ड- नीरज शर्मा-9826266571
खरगौन, संजय शर्मा-7694897272
सतना, दीपक गौतम-9923800013
रीवा-धनंजय तिवारी-9425080670
रतलाम, अमित निगम-70007141120
झाबुआ-नोमान खान-8770736925

कार्यालय का पता:- लाजपत भवन प्रथम तल, आईसीआईसीआई बैंक के पास, एमपी नगर, ज़ोन-1, भोपाल, मप्र,
संपर्क करें- 07554064144, 9229497393, 9425048589

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, स्थानीय संपादक- **अरविंद मिश्र, संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेल:- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)